भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 372
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025

गुजरात में बीएसएनएल की हाई-स्पीड सेवाएं

***372. श्री परषोत्तमभाई रूपाला:**

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या केंद्र सरकार को इस मुद्दे के संबंध में राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या का समाधान करने और गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"गुजरात में बीएसएनएल की हाई-स्पीड सेवाएं" के संबंध में दिनांक 26 मार्च, 2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *372 (पोजीशन नं.. 12) के भाग (क) से (ग) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) से (ग) गुजरात में 97% से अधिक गांव सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कवर किए गए हैं जिनमें बीएसएनएल की 2जी/3जी/4जी मोबाइल सेवाओं से कवर किए गए 56% गांव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल ने चरण-IX.2 परियोजना के अंतर्गत 4,492 2जी/3जी साइटों का 4जी में उन्नयन करने की योजना बनाई है, जिसमें से दिनांक 08.03.2025 तक 3,955 4जी साइटें चालू हो चुकी हैं। इसके अलावा, 4जी सेचूरेशन परियोजना के अंतर्गत, गुजरात में 701 मोबाइल टावर लगाने की योजना बनाई गई थी, जिसमें से दिनांक 28.02.2025 तक 509 टावर चालू हो चुके हैं।

इसके अलावा, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की पहुंच प्रदान करने के लिए, भारतनेट चरण-I और II के अंतर्गत नियोजित सभी 14,320 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। भारतनेट के अंतर्गत, गुजरात में कुल 55,418 किलोमीटर ओएफसी बिछाई गई है और भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करके ग्राम पंचायतों/गांवों में 1,23,277 एफटीटीएच (फाइबर-टू-द-होम) हाई स्पीड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.08.2023 को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत गुजरात सहित पूरे भारत के लिए भारतनेट चरण- I और II के मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों/गैर-ग्राम पंचायत गांवों में (मांग के आधार पर) नेटवर्क का निर्माण, 10 वर्षों के लिए प्रचालन और रखरखाव तथा उपयोग को मंजूरी दी गई है। गुजरात में, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत शेष 4 ग्राम पंचायतों और गैर-ग्राम पंचायत गांवों को (मांग के आधार पर) कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार सेवा बढ़ाने के मामले में भारत सरकार को राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

*****